न्यूज ब्रीफ

बहुमत के बावजूद प्रदेश में विकास नहीं करा पाई भाजपा : गहलोत

बिजौलिया (भीलवाड़ा)| पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को उपखंड क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याक्षी विवेक धाकड़ के समर्थन में तिलस्वां में आमसभा और कस्बे की बोहराजी की बगीची में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गहलोत ने पहले तिलस्वा महादेव मंदिर में दर्शन कर मंदिर के बाहर हुई आमसभा में कहा कि भाजपा की सीटें विधानसभा में बहुमत से ज्यादा होने के बावजूद भी भाजपा सरकार विकास नही करा पाई है। अपराध बढ़े हैं। मंत्री पुलिस व्यवस्था को बेहतर बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

अजमेर उपचुनाव की तैयारी का जायजा लेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर| मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत सोमवार को अजमेर में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। अजमेर सहित अलवर लोकसभा व मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर 29 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। अजमेर में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है। इस वजह से प्रत्येक बूथ पर वहां दो बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट वहां पर भेज दी गई है। निर्वाचन विभाग की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकें कर तैयारियों का आकलन करेगी।

मुख्यमंत्री की कल बीगोद में आमसभा

भीलवाड़ा| मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 23 जनवरी को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीगोद में आएंगी। वे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी शक्तिसिंह हाड़ा के समर्थन में आम सभा करेंगी। जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि 23 जनवरी दोपहर 12:15 बजे आम सभा होगी।

सम्मान | कोलकाता में विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र के साथ आईटी टीम रही मौजूद

सीएम राजे को ई-रत्न ऑफ इंडिया सम्मान, आईटी में प्रदेश को 6 अवॉर्ड

भामाशाह बीमा योजना, राज ई-ज्ञान, राज महिला सुरक्षा योजना को सर्वश्रेष्ठ तकनीक पुरस्कार

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

कोलकाता में ई-रत्न ऑफ इंडिया सम्मान प्राप्त करते विस उपाध्यक्ष राव राजेंद्र व अन्य।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, डिजिटल इंडिया और देश के डिजिटल परिवर्तन पहल के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ई-रत्न ऑफ इंडिया पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश के विकास एवं सरकारी योजनाओं में आईटी के प्रभावशाली उपयोग के चलते यह राजे को यह सम्मान मिला है। यही नहीं राज्य की विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं को भी अवार्ड मिले। इनमें ई-गवर्नेंस श्रेणी का स्टेट केटेगरी अवार्ड, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में राज महिला सुरक्षा और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान एक उदाहरण बनकर उभरा है।

कोलकाता में शनिवार को कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 52 वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री राजे की गैर मौजूदगी में विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह के साथ आईटी विभाग के ओएसडी रामचरण शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर अरुण चौहान, ज्वाइंट डायरेक्टर आर. के . शर्मा सहित अधिकारियों की टीम ने पुरस्कार प्राप्त किए। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से शुरू किए गए थे।

राज्य को इन योजनाओं में भी अवॉर्ड

- ई-गवर्नेंस श्रेणी में देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्टेट केटेगरी अवॉर्ड।
- शिक्षा के क्षेत्र में राज ई-ज्ञान पुरस्कार।
- महिला सुरक्षा के क्षेत्र में राज महिला सुरक्षा सर्वश्रेष्ठ तकनीक अवॉर्ड।
- फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क को सीएसआई निहिलेंट अत्याधुनिक तकनीक अवॉर्ड।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को ई-गवर्नेंस अवॉर्ड।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ।

गांवों में भी डिजिटलीकरण : प्रदेश डिजिटलीकरण गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी डिजिटलीकरण ने पैर पसार लिए हैं। यही वजह है देश के प्रतिष्ठित सीएसआई- निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड-2017 की ओर से प्रदेश की कई योजनाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था।

उपचुनाव से पहले राज्य के कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश कार्यक्रम स्थगित

जयपुर | उपचुनाव के ठीक पहले राज्य कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से 22 से 24 जनवरी तक किए जाने वाले सामूहिक अवकाश का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में वार्ता करने के लिए कर्मचारियों को सरकार आमंत्रित करेगी। सात सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारी 22, 23 व 24 जनवरी को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश पर जाने वाले थे। इससे पहले ही सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता हुई, जिसमें अवकाश को स्थगित करने का फैसला किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक आयुदान सिंह कविया ने बताया कि सात सूत्री मांग पत्र पर वार्ता करने हेतु राज्य सरकार ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को फरवरी के दूसरे सप्ताह में आमंत्रित करने का आश्वासन दिया है। इसकी सूचना सरकार की ओर से जल्द भिजवायी जाएगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों एवं जिले के संयोजकों व सह संयोजकों की एक संयुक्त बैठक 20 जनवरी को अजमेर में रखी गई थी, जिसमें सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद कार्यक्रम स्थगित करने पर सहमति बनी।

कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की नसीहत, कहा-मतभेद भुलाएं

अलवर में वसुंधरा ने संभाली उपचुनाव की कमान

अलवर| मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को अलवर पहुंचकर उपचुनाव की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने यहां शांतिकुंज स्थित एक होटल में अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने महिला क्लबों की पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और मातृशक्ति यानी मां के सहयोग से उपचुनाव वाले तीनों क्षेत्रों ""मां' में भाजपा की जीत होगी। सीएम ने कहा कि 'मां' मतलब एम से मांडलगढ़, ए से अजमेर और ए से अलवर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति जिसके पास हो, वह हर क्षेत्र में जीतता है।

मुख्यमंत्री सबसे पहले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिली। इस जनसंवाद के दौरान कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच मनमुटाव की बातें सामने आई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने इन कार्यकर्ताओं को समान रूप से जिम्मेदारी देने का आश्वासन देकर कहा कि हर बूथ पर पहुंचकर मजबूती के साथ जुट जाएं। इसके बाद विधायक ज्ञानदेव आहूजा के साथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने उनसे विकास कार्यों की जानकारी ली और कहा कि क्षेत्र में सड़क, चिकित्सा, पानी, बिजली के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं और आचार संहिता के बाद फिर विकास कार्य कराए जाएंगे। विधायक आहूजा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विकास पर चर्चा के बाद कहा कि चुनाव के दौरान रामगढ़ क्षेत्र में सभा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजबूती से डोर टू डोर प्रचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और अन्य लोग मुख्यमंत्री से मिले। कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी की विधायक होने के कारण विकास कार्य ठप होने की बात कही, साथ ही पुराना राजगढ़ में नल कनेक्शन सहित स्थानीय समस्याएं बताई। सैनी समाज के लोगों ने किया स्वागत, विधायक की टिकट के लिए जताई दावेदारी जताई।

10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र के बिना अफसर-नेताओं के खिलाफ परिवाद पर जांच भी नहीं होगी

पंचायतीराज विभाग ने 4 साल पुराने परिपत्र पर फिर जारी किया आदेश

मनोज शर्मा | जयपुर

पंचायतीराज विभाग में जनप्रतिनिधियों, अफसर एवं कार्मिकों के खिलाफ किसी तरह की शिकायत करने के लिए भी दस रुपए खर्च करने होंगे। शिकायत करने वाले को नाम, पते, मोबाइल अथवा टेलीफोन नंबर के साथ 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र के बिना उनके परिवाद को कूड़े की टोकरी में डाल दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह परिपत्र चार साल पहले ही निकाल दिया था। लेकिन कई अफसर एवं विभागाध्यक्ष, बिना शपथ पत्र वाली शिकायतों पर कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए, अब आदेश निकालना पड़ा है। आदेश निकालने वाले पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त का कहना है कि सरकार सही कार्य कर रही है। क्योंकि, अनुत्तरदायी एवं झूठी शिकायतों नेता, अफसर एवं कार्मिकों के उत्साह पर विपरीत असर पड़ रहा है। हालांकि, विभागीय अफसर झूठी शिकायतों का आंकड़ा बताने में नाकाम रहे।

बेनामी शिकायत कूड़ेदान में डालेंगे

पंचायतीराज विभाग में किसी भी बेनामी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायत में नाम, पते एवं शपथ पत्र के साथ सबूत भी देने होंगे। मतलब साफ है कि पंचायत राज में किसी अफसर, नेता या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत भेजनी है तो उसे अपनी पहचान बतानी होगी। विभागीय अफसर ऐसे शिकायतकर्ता की पहचान उजागर नहीं करेंगे, इस पर संशय है।

नेताओं की शिकायत फ्री में दर्ज होगी

आम जनता को किसी भी अफसर या नेता अथवा कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए दस रुपए का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। लेकिन, खास लोगों जैसे सांसद, विधायक, सरपंच सहित पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्य को शिकायत के साथ 10 रुपए का शपथ पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। सीएम हैल्थ लाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर भी शपथ पत्र की बाध्यता लागू नहीं होगी।

झूठी शिकायतों पर मैन पावर खर्च

परिवादों की जांच एवं परीक्षण से सरकार ने यह निर्णय निकाला है कि बहुत से प्रकरण केवल व्यक्तिगत रंजिश एवं दुर्भावना से प्रेरित होकर दर्ज करवाए जाते हैं। परिवाद झूठे नामों एवं गलत पते देकर भिजवाए जाते हैं। कई बार शिकायतकर्ता तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। शिकायत के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाए जाते। कई शिकायत भी डाक के जरिए मिलती है। इसकी जांच में बड़ा मैनपावर लगाना होता है। शपथ पत्र से कोई परिवाद आएगा तो झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। आपराधिक मामले भी दर्ज करवाए जा सकेंगे।

कितनी शिकायतें झूठी मिलीं, मैं नहीं जानता : मक्कड़

पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र शेखर मक्कड़ का कहना है कि झूठी शिकायतों का ब्यौरा तो एकत्रित नहीं किया। लेकिन, बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों एवं अफसरों के खिलाफ झूठे परिवाद आ रहे है। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प नहीं मिलने के सवाल पर बोले कि इसका रास्ता निकालने के लिए विधिक राय ली जा रही है।

हिदायत | विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तरीय बैठकों में अस्थायी रोक रहेगी

जिन समितियों में विधायक सदस्य, उनकी गैर मौजूदगी में मीटिंग नहीं बुला सकेंगे अफसर

संसदीय कार्य विभाग ने प्रमुख विभागीय अफसरों सहित कलेक्टर्स को जारी किया परिपत्र

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

विधानसभा सत्र की अवधि में राज्य सरकार का कोई विभाग ऐसी मीटिंग नहीं नहीं कर सकेगा, जिसमें विधायक सदस्य होते हैं। संसदीय कार्य विभाग ने प्रमुख विभागों के अफसरों सहित कलेक्टर्स के लिए एक परिपत्र जारी कर ऐसा नहीं करने की साफ तौर पर हिदायत दी है। देखने में आया है कि कई विभाग विधानसभा सत्र के दौरान मीटिंग बुलाकर विधायक की बिना सहभागिता के निर्णय ले लेते हैं। विधानसभा के दौरान विधायकों की ओर से इस मसले पर सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया जाता रहा है ।

राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 फरवरी से आहूत होगा। संसदीय कार्य विभाग का मानना है कि विधायकों को विभिन्न राज्य, जिला एवं तहसील स्तरीय समितियों में सदस्यों के रुपए में मनोनीत किया जाता है। सत्र के दौरान इन समितियों की बैठक होती है तो सदन में रहने की वजह से विधायक इनमें भाग नहीं ले सकते। जबकि, उनकी भागीदारी जरूरी होती है। समिति सदस्य होने के बावजूद एक तरह से बिना उनकी भागीदारी के निर्णय कर लिए जाते हैं। विभाग ने ऐसे दिशा-निर्देश पहले भी जारी किए हैं, लेकिन विभागीय अफसर उनकी पालना नहीं करवा रहे हैं। इसकी पालना में यह परिपत्र निकाला गया है।

संसदीय कार्य विभाग ने प्रमुख सचिव, सचिव, विशिष्ट सचिव, संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, नगरीय विकास विभाग और पंचायती राज आयुक्त को विशेष रूप से विधानसभा सत्र के दौरान बैठकें आयोजित नहीं करने को कहा है ।

विशेषाधिकार हनन मानकर अफसरों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही

संसदीय कार्य विभाग के अनुसार विशेष परिस्थितियों में कोई बैठक आयोजित करनी है तो समिति में मनोनीत विधायक की सहमति संबंधित विभाग के अफसर को लेनी होगी। भविष्य में बिना सहमति पर कोई अफसर मीटिंग आयोजित करते हैं तो यह विधायक के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है।

एक माह में बजरी का विकल्प लाने जा रही सरकार, कोन क्रेशर से होगा उत्पादन

पॉलिटिकल रिपोर्टर. जयपुर| राज्य सरकार एक माह में बजरी का विकल्प लाने जा रही है। कोन क्रेशर के जरिए बजरी का उत्पादन किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सड़क से लेकर मकान निर्माण के कार्य में किया जाएगा। इसकी प्रदेश में शुरूआत करने के लिए खान विभाग के अफसर कारोबारियों को सहमत करने में जुटे हैं। खास यह है कि नदियों से निकलने वाली बजरी से क्रोन क्रेशर के जरिए तैयार की जाने वाली बजरी महंगी नहीं होगी। एक अनुमान के अनुसार 400 रुपये प्रति टन ही बजरी आम उपभोक्ता तक पहुंचेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बजरी खनन पर रोक लगा रखी है। इसके कारण हजारों सरकारी प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। काम ठप हो गया है। आम आदमी अपना घर का निर्माण नहीं कर पा रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार के अफसरों ने बजरी का विकल्प लाने जा रही है, जिससे आम आदमी की परेशानी दूर हो। साथ ही सरकारी प्रोजेक्ट भी तेजी से चल पड़े। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य के हजारों खानों के पास लाखों टन स्टोन डस्ट पड़ा हुआ है, जिसका आज की तिथि में कोई खास उपयोग नहीं होता है। इसी स्टोन डस्ट का उपयोग अब बजरी बनाने के लिए किया जाएगा। इसको लेकर खान विभाग के अधिकारियों ने कारोबारियों के सामने एक प्रजेंटेशन भी दिया।

पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

सिटी रिपोर्टर . जयपुर | तेल कंपनियों की तरफ से लगातार पेट्रोल-डीजल की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस की ओर से शहर में 16 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के 16 मुख्य चौराहों पर प्रदर्शन किया ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुतले जलाए।

जयपुर के कलेक्ट्री सर्किल, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, रामगंज, सहकार मार्ग, बगरू, मालवीय नगर, गुर्जर की थड़ी, सांगानेर, मानसरोवर, शास्त्री नगर, सहकार मार्ग, भांकरोटा, हवामहल, छोटी चौपड़ , ओर आगरा रोड़ पर पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाये जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्री सर्किल पर कांग्रेस के सैकंडों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से आम-आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। लेकिन केन्द्र सरकार ओर राज्य सरकार को लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं हैं। खाचरियावास ने कहा कि जब क्रूड आयल के भाव कम हुए तब केन्द्र ओर राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, अब क्रूड आयल के थोड़े से भाव बढ़ते ही पेट्रोल डीजल दाम बढ़ा दिए गए। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम कम नहीं होंगे कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा।

कांस्टेबल व उसके परिवार की आत्महत्या का प्रकरण गंभीर : बेनीवाल

जयपुर| खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सुरपालिया थाने में दलित सिपाही द्वारा पत्नी-बच्चों के साथ आत्महत्या के प्रकरण को गंभीर बताते हुए गहरा दुख जताया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार नागौर एसपी को तत्काल हटाए और गृहमंत्री घटना पर स्थिति स्पष्ट करें। किस कारण से आत्महत्या की और उसके सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था उसकी एसओजी या सीबीआई जांच अत्यंत आवश्यक है। बेनीवाल ने पुलिस सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी अंग्रेजों के बनाए कानून पुलिस में चल रहे हैं।

नर्सेज एसोसिएशन में प्यारेलाल चौधरी प्रदेशाध्यक्ष व शशिकांत शर्मा प्रदेश संयोजक बने

जयपुर | राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने हर तरह से मंथन के बाद प्यारेलाल चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष व शशिकांत शर्मा को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। एसएमएस सर्जिकल लेक्टर हॉल में 19 जनवरी को हुई बैठक में 4 माह में सभी जिलों में चुनाव कराने का निर्णय भी लिया है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक रामसज्जन यादव, कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह शेखावत व बलराम चतुर्वेदी ने रविवार को बताया कि मांगों

में नर्सेज को नियमित करना, पदनाम परिवर्तन कर नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स ग्रेड सैकंड को नर्सिंग ऑफिसर बनाने, नर्सिंग के लिए अलग से निदेशालय तथा वेतन विसंगति को दूर करना है।

6 आरएएस के तबादले

जयपुर| रविवार देर रात कार्मिक विभाग में छह आरएएस के तबादले किए। इनमें सबसे अहम तबादला गिरीश पाराशर का है जिन्हें अब मेडिकल से हटा दिया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल से हटाने की मांग की थी। डॉक्टर्स हड़ताल में उनकी एक मांग पाराशर को हटाने को लेकर भी थी। अब वे रीको में सलाहकार कार्मिक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय में अतिरिक्त निदेशक छात्रवृत्ति महावीर सिंह प्रथम को एपीओ कर दिया गया है । उनकी जगह गोपालन निदेशक राजेंद्र किशन का उनके पद पर तबादला किया गया है। वही हाल ही में वक्फ बोर्ड में सीईओ लगाए गए सत्तार खान का फिर तबादला कर दिया गया। उन्हें अतिरिक्त आयुक्त प्रवर्तन यातायात की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले ही सूची में उन्हें वक्फ बोर्ड में सीईओ पद की जिम्मेदारी दी थी। अब यह जिम्मेदारी अमानुल्लाह खान संभालेंगे। जबकि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ही संपदा अधिकारी पद पर हाकम खान का तबादला किया गया है।

सेक्स समस्यायें
छोटी इन्द्री, निराश क्यो?
कीमत मात्र 900/- से 1100/-
जापानी इन्द्रीवर्धक यंत्र
अंग का छोटापन, पतलापन, टेढ़ापन, नपुंसकता, संतानहीनता, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, सेक्स इच्छा में कमी, नसों की कमजोरी एवं नामर्दी को दूर कर मनचाहा सेक्स टाईम बढ़ाये। NO SIDE EFFECT
FREE 30 दिनों की दवा के साथ जोशीला स्प्रे 32 GB मेमोरी कार्ड फ्री मंगाये
9973558222
8877247825

सेक्स समस्याऐं
छोटा अंग, निराश क्यों ?
अंग के छोटेपन, पतलेपन, टेढ़ेपन को दूर करके ताकतवर, सुडौल बनाये। मनचाहा आनन्द का समय बढ़ाये। शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, नपुंसकता, शुक्राणुहीनता का सफल इलाज।
45 दिनों की दवा के साथ काम कला पुस्तिका पाएं।
अंगवर्द्धक यंत्र प्राप्त करें
फोन लगाएं तुरंत समाधान पायें।
09560407653
07835978829

छोटा अंग, निराश क्यों?
जापानी पट्टीनुमा इन्द्रीवर्धक यंत्र फ्री
इन्द्री का छोटापन,पतलापन टेढ़ापन, ढीलापन, सेक्स इच्छा में कमी नपुंसकता, संतानहीनता, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, अंगों की कमजोरी, अंगों का विकास न होना, नसों की कमजोरी, नामर्दी एवं अन्य सभी समस्त समस्याओं का संपूर्ण आयुर्वेदिक सफल इलाज हेतु शीघ्र संपर्क करें। NO SIDE EFFECT
मनचाहा सेक्स टाईम बढ़ायें
लाभ नहीं तो पैसा नहीं
07079062749
09643345277

सिकंदरे आज़म
विश्व का सर्वश्रेष्ठ
भारत में इन्द्रीवर्धक कैप्सूल उपलब्ध
नया विश्वास, एक ही कैप्सूल से
इन्द्री में हैरतअंगेज वृद्धि व स्फूर्ति
नसों की खराबी, शीघ्रपतन, स्वपनदोष, नपुंसकता दूर करें। मनचाहा सैक्सटाइम
मेडिकल स्टोर से खरीदें या फोन करें
09212358677
09015270020

nps national pension system
Save Right Retire Bright

"सही उम्र में एनपीएस के साथ किए गए निवेश ने आज मुझे मन की शांति दी है!"

एनपीएस क्या है?
एक उच्च कार्यकुशल तकनीक आधारित प्रणाली जिससे आप आज छोटी-छोटी बचत कर जीवन की दूसरी पारी के लिए निधि जमा कर सकते हैं।

एनपीएस क्यों?
- कम लागत उत्पाद
- व्यक्तियों, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए कर लाभ
- बाजार आधारित आकर्षक प्रतिलाभ
- आसान संवहनीयता
- अनुभवी पेंशन निधियों द्वारा व्यावसायिक रूप से संचालित
- संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विनियामक पीएफआरडीए द्वारा विनियमित
- ₹500/- के न्यूनतम अंशदान से भी खोल सकते है

कौन शामिल हो सकता है?
आप शामिल हो सकते हैं यदि आप निम्नलिखित में से किसी एक या सभी शर्तों को पूरा करते हैं:
- भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी
- शामिल होने की तिथि को 18-65 वर्ष के बीच आयु
- वेतनभोगी या स्वः रोजगार

कर लाभ एवं एनपीएस?
- समय-समय पर संशोधित किये गये अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीई के अंतर्गत उपलब्ध ₹1.50 लाख की सीमा के अतिरिक्त आप एनपीएस के माध्यम से ₹50,000/- की बचत पर अतिरिक्त लाभ पा सकते हैं तथा अतिरिक्त कर के रूप में ₹15,450/- तक बचत कर सकते हैं
- प्रभावी रूप से, आप एनपीएस में निवेश करके कर कटौती के रूप में ₹2.00 लाख तक दावा कर सकते हैं

मैं अपना एनपीएस खाता कहाँ खोल सकता हूँ?
- पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत किसी पंजीकृत प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस-सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) के पास जाएं तथा प्रारंभिक अंशदान के साथ अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करें

* आधार कार्ड या पैन एवं बैंक खाते का इस्तेमाल करके ई-एनपीएस प्लेटफार्म के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन एनपीएस खाता खोल सकते हैं।

एनपीएस या अपने नज़दीकी पीओपी-एसपी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं.1800 110 708 पर कॉल करें या एनपीएस लिखकर 56677* (*मानक शुल्क लागू) पर एसएमएस करें या हमारी वेबसाइट www.npstrust.org.in देखें

NPS TRUST National Pension System Trust
Regulated by PFRDA

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

NPS-Gen-02-Jan